भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 861
उत्तर देने की तारीख 09 फरवरी, 2024

भारतनेट परियोजना के अंतर्गत शामिल गांव

861. श्री परिमल नथवानी:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अभी भी देश के कई गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध नहीं है;
(ख) भारतनेट परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ग) अब तक इस परियोजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है; और
(घ) परियोजना के तहत प्रारंभ से ही जारी और व्यय की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार राज्य मंत्री
(श्री देवुसिंह चौहान)

(क) से (घ) पिछले 10 वर्षों में भारत में दूरसंचार कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार हुआ है जिसकी रूपरेखा इस प्रकार है:

	मई 2014	दिसंबर 2023
बेस ट्रांसीवर स्टेशनों की संख्या	6.49 लाख	28 लाख
बिछाई गई ऑप्टिकल फाइबर	10.62 लाख किमी	39 लाख किमी
इंटरनेट प्रयोक्ता	25.15 करोड़	88.12 करोड़
डाटा का मूल्य	269 रुपए/जीबी	9.94 रुपए/जीबी
मीडियन इंटरनेट स्पीड	1.3 एमबीपीएस	75.8 एमबीपीएस
भारतनेट के तहत जोड़ी गई ग्राम पंचायतें	58	2.10 लाख

भारत में 5जी सेवाओं का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2022 को हुआ। 14 महीनों की अवधि के भीतर 4.2 लाख से अधिक 5जी साइटें 742 जिलों में कनेक्टिविटी प्रदान कर रही हैं। यह दुनिया में 5जी का सबसे तेज़ रोल-आउट है।

देश में दूरसंचार कनेक्टिविटी को और अधिक बेहतर बनाने के लिए सरकार कई स्कीमें कार्यान्वित कर रही है। लगभग 55 हजार गांवों को 4जी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 41,331 करोड़ रुपये के परिव्यय से कुल 41,160 मोबाइल टावरों को मंजूरी दी गई है।

हाल ही में सरकार ने 1.88 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से सभी बसे हुए गांवों को सेवा प्रदान करने के लिए भारतनेट कार्यक्रम में संशोधन किया है जो इस प्रकार है:

- मौजूदा भारतनेट नेटवर्क का उन्नयन।
- भारतनेट उद्यमीज अर्थात् ग्राम स्तर के उद्यमियों के माध्यम से नेटवर्क के उपयोग पर फोकस।
- संपूर्ण नेटवर्क का संचालन एवं रखरखाव।
- समर्पित नेटवर्क संचालन केंद्र।
- सभी बसे हुए गांवों को जोड़ने के लिए कार्यक्षेत्र का विस्तार।
- 1.5 करोड़ घरेलू फाइबर कनेक्शन प्रदान करना

भारतनेट स्कीम का संबंधित राज्य-वार विवरण दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

******